और... एक शे'र

ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता
एक ही शख्स था जहान में क्या
-जौन एलिया

लोकमत समाचार
तमसो मा ज्योतिर्गमय

यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती. ■ मार्क ट्वेन

संपादकीय

आतंकवाद को चीन का बेशर्म समर्थन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का वादा करने के बावजूद 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी के मामले में संयुक्त राष्ट्र में भारत की मांग के खिलाफ जाकर चीन ने साबित कर दिया है कि वह पाकिस्तान का किसी भी हद तक जाकर साथ दे सकता है. चीन की इस कार्रवाई से लखवी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर अड़े पाकिस्तान को नैतिक समर्थन मिला है तथा संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर कार्रवाई की भारत की मांग पर रोक लग गई है. दरअसल चीन से हमें समर्थन की अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए थी. उसके खिलाफ जाकर हमने तिब्बत की निर्वासित सरकार को अपने देश में शरण दे रखी है. असल में भारत के विशाल बाजार को देखते हुए चीन का हमारे साथ अच्छे संबंधों का दिखावा करना मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के बाजार अपनी क्षमता तक भर चुके हैं. हाल ही में चीन द्वारा मानसरोवर यात्रा में भारतीय श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को इजाजत देते हुए नाथू ला होकर तिब्बत जाने का दूसरा मार्ग खोल देने के कारण शायद हमने सोच लिया था कि वह हमारा अच्छा सहयोगी बन सकता है. लेकिन हकीकत यही है कि बाजार की मजबूरी के कारण चीन छोटी-मोटी बातों पर हमारे साथ सदाशयता भले ही दिखाए, गंभीर मुद्दों पर वह हमारा साथ कभी नहीं देगा. भीतर से वह भारत को प्रतिद्वंद्वी मानता है क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों पर वर्चस्व जमाने के मार्ग में भारत ही उसके मार्ग में बाधा है. पाकिस्तान का समर्थन भी वह हमें कमजोर बनाने की नीयत से ही करता है. इसलिए व्यापारिक मामले अपनी जगह हैं, लेकिन चीन की नीयत पर भरोसा हम कभी नहीं कर सकते. इसके बावजूद चीन ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का जो बेशर्म समर्थन (बेशर्म इसलिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के पांच स्थायी सदस्यों में से चीन को छोड़कर चारों भारत के साथ हैं और अल कायदा से जुड़े होने के कारण संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति भी लखवी को 2008 में आतंकी घोषित कर चुकी है) किया है, वह भविष्य में उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है. चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद उसके देश में भी पैर पसार चुका है. जिस तरह आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान को वह भस्मासुर की तरह तबाह कर रहा है, असंभव नहीं है कि चीन को भी जल्दी ही अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़े. देशों के बीच निजी संबंध और हानि-लाभ का गणित अपनी जगह है, लेकिन दुनिया के व्यापक हित के मुद्दे पर किसी भी राष्ट्र को अपने क्षुद्र स्वार्थों को नहीं देखना चाहिए. अगर चीन इस बात को नहीं समझेगा तो वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा. ■■

ब्रेक

लघुकथा

यू. एस. आनंद

पिता को पत्र लिखे पंद्रह से भी अधिक दिन हो गए थे, किंतु अब तक उनका मनीऑर्डर नहीं आने से राजन पिता की इस सुस्ती पर मन-ही-मन कुढ़ रहा था. अन्यमनस्क-भाव से कमरे में ताला लगाकर जैसे ही वह मुड़ा, सामने पोस्टमैन को देख उसकी बांछें खिल गईं. उसने झटपट मनीऑर्डर के रुपए लिए और प्रसन्नता से सीटी बजाता सड़क पर निकल आया. मन-ही-मन उसने कार्यक्रम भी तय कर लिए. सबसे पहले तो 'अनामिका' में भोजन करेगा. फिर शाम को दोस्तों के साथ रीजेंट चलेगा. संयोग से आज ही अमिताभ की फिल्म लगी है. ब्लैक में टिकट लेकर ही सही, लेकिन फिल्म वह आज ही देखेगा.

अचानक फुटपाथ पर एक कृशकाय मानव-आकृति को देखकर वह ठिठक गया. उसका पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था. फुटपाथ पर बैठा वह बड़े जतन से उंगलियों पर हिसाब करता हुआ पैसे गिनने में व्यस्त था. राजन के पैरों की आहट मिलते ही वह सचेत हो गया. उससे आंखें मिलते ही राजन सिहर उठा. उस दुर्बल आकृति से नजर फेरकर झटके से वह आगे बढ़ ही जाना चाहता था कि तभी उस व्यक्ति ने क्षीण स्वर में आवाज लगाई- ''बाबूजी..... बाबूजी.....''

राजन प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए पूछ बैठा- ''क्या है ?''

उसने दीनता से अपने मैले चिकट अंगोछे से मुड़ा-तुड़ा मनीऑर्डर फॉर्म निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा- ''बाबूजी, मेरा बेटा श्रीरामपुर में पढ़ता है, पिछले दिनों उसका पत्र आया है..... उसे पैसे की आवश्यकता है.... ये पैसे मैंने उसे भेजने के लिए जुगाड़ किए हैं.... जरा इस फार्म को.....''

आगे के शब्द को वह साफ-साफ नहीं सुन पाया. उसकी आंखों के आगे अपने बूढ़े पिता का निश्तेज चेहरा टंग गया था. ■■

क्या यही है संस्कार की दीक्षा?

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

बहुत कम लोगों को यह बताया गया है कि योग दिवस (21 जून) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक - डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की पुण्यतिथि भी है. लेकिन संघ से भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही कुछ महीनों में राम माधव संघ के संस्थापक द्वारा निर्धारित आदर्शों को भूल गए. 'राजपथ' पर योगाभ्यास के बावजूद वह 'राज दंभ' में अपने मोबाइल से दिग-दिगंत तक जहर फैलाने लगे. अपनी पार्टी की सरकार के सड़क दरबार की भीड़ में उन्हें कष्ट हुआ कि राष्ट्र के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी क्यों नहीं दिखाई दिए. उन्होंने दरबार के किसी अर्दली से भी पूछने की कोशिश नहीं की कि उपराष्ट्रपति के वहां न दिखने का कारण क्या हो सकता है? पार्टी महासचिव- प्रवक्ता तथा संघ-भाजपा के निर्णायक सूत्रधार मानकर वह अपने को सर्वज्ञ समझते हैं. ट्विटर पर उनकी तीखी टिप्पणियों से भारत ही नहीं सुदूर देशों तक पहली नजर में यही संदेश गया कि भाजपा के प्रभावशाली नेता 'योग' को सामुदायिक चश्मे से देखते हुए उपराष्ट्रपति को अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि मानते हैं और शायद योग केवल महान हिंदू धर्म और संघ द्वारा प्रचारित ज्ञान है. राम माधव ने बाद में भले ही अपनी कड़वी टिप्पणियां वापस ले लीं, लेकिन उनके संघ-भाजपा विहिप-बजरंग दल के समर्थकों ने तुरंत समर्थक संदेश जारी करते हुए उपराष्ट्रपति, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इत्यादि की राजपथ पर अनुपस्थिति की भर्त्सना कर दी. बाद में भारत सरकार की ओर से खेद के साथ यह स्पष्टीकरण जारी हुआ कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को औपचारिक निमंत्रण ही नहीं दिया गया था. कारण यह था कि उपराष्ट्रपति का पद

संघ से भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही कुछ महीनों में राम माधव संघ के संस्थापक द्वारा निर्धारित आदर्शों को भूल गए.

संवैधानिक दृष्टि से प्रधानमंत्री से ऊपर है और प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि हों, वहां उपराष्ट्रपति को दर्शक-श्रोता समुदाय में नहीं खड़ा किया जा सकता है. उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सभापति भी होते हैं. सदन में उनके प्रवेश करने पर अन्य सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री को खड़े ही नहीं होना पड़ता, सदन की कार्यवाही के दौरान उनके निर्देशों-आदेशों का पालन भी करना होता है.

राम माधव और उनकी परम शिष्य मंडली को क्या इतना सामान्य ज्ञान भी नहीं है. कुछ दिनों पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि ''समय के साथ वेशभूषा और संगठनों की सुख-सुविधाओं में बदलाव होता ही है.'' सचमुच राम माधव ने तो संघ में रहते हुए कई वर्ष पहले हेलिकॉप्टर उड़ाने के लिए पायलट की ट्रेनिंग ले ली थी. वह और संघ से निकले या जुड़े कई लोग हवाई यात्राओं-पांच सितारा सुविधाओं के अभ्यस्त हो गए हैं. वे इसे समय की मांग-मजबूरी कह सकते हैं. लेकिन क्या संस्कार भी बदलना जरूरी है?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने स्वयंसेवकों को दिशा निर्देश देते हुए कहा था- ''अपनी-अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, परंतु उसे थोपने का प्रयास समाज के भीतर की सकारात्मक बहुलता को समाप्त कर देता है. अपनी समझ, सोच और विचार को पूरे समाज की समझ एवं सोच नहीं मानना चाहिए.'' इन दिनों भाजपा ही नहीं उससे जुड़े संगठनों के कई नेता सत्ता के अहंकार में संपूर्ण भारतीय समाज पर अपने विचार थोपने की कोशिश कर रहे हैं. इस आवेश में वे असहमति रखने वाले लोगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. एक सज्जन ने तो 'योग' न करने वालों को देश से बाहर निकल जाने तक का फरमान जारी कर दिया. चुनावी राजनीति के चक्कर में कुछ नेता अल्पसंख्यक समाज के कुछ चेहरों को साथ में रख लेते हैं, तो कुछ उनसे टकराने के तेवर दिखाते हैं. जबकि डॉ. हेडगेवार ने समर्थ रामदास की उक्तियों को 1930 में अपनी डायरी में लिखा तथा जीवन भर स्वयंसेवकों को याद दिलाई ''जैसा कहें वैसा करें, प्रयास करें तब बोलें. करनी के बिना कथनी कुत्ते की कै जैसी महत्वहीन और अप्रभावी है. जांचने के बाद ही ग्राम में प्रवेश (कार्य आरंभ) करना चाहिए. कष्ट बिना फल नहीं, कष्ट बिना राज्य नहीं. किंतु बिना जग में कुछ भी साध्य नहीं होता.''

लेकिन गुरु गोलवलकर, देवरस, प्रो. राजेंद्र सिंह, सुदर्शनजी और मोहन भागवत की परंपरा वाले प्रभावशाली कई स्वयंसेवकों को सत्ता की राजनीति ने सचमुच बहुत बदल दिया. राजनीतिक परंपरा की दृष्टि से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गांधी का अनुपालन करते हुए देशवासियों से कहा था- ''संस्कृति मुखर नहीं, शांत होती है, आत्मसंयमित और सहनशील होती है. कोई व्यक्ति कितना सुसंस्कृत है या नहीं, इसका पता यह देखकर चल जाता है कि वह कितना मौन रहता है. राष्ट्रीय संस्कृति से भी अधिक महत्वपूर्ण है - मानवीय संस्कृति.'' इसलिए सभी पार्टियों के नेताओं को राजनीति के मूलभूत आदर्शों और मूल्यों को सामने रखकर नई परिस्थितियों में भी भारतीय संस्कारों की रक्षा करने की बात सोचनी चाहिए. ■■

मीडिया के लिए बेमानी हो चुका है आपातकाल?

पुण्य प्रसून वाजपेयी
कार्यकारी संपादक, आज तक

क्या मौजूदा वक्त में मीडिया इतना बदल चुका है कि मीडिया पर नकेल कसने के लिए अब सरकारों को आपातकाल लगाने की भी जरूरत नहीं है? यह सवाल इसलिए क्योंकि चालीस साल पहले आपातकाल के वक्त मीडिया जिस तेवर से पत्रकारिता कर रहा था, आज उसी तेवर से मीडिया एक बिजनेस मॉडल में बदल चुका है, जहां सरकार के साथ खड़े हुए बगैर मुनाफा बनाया नहीं जा सकता है.

मौजूदा वक्त में पीआईओ के साथ खड़े होकर जिस तरह पत्रकार खुद के सरकार के साथ खड़े होने की प्रतिस्पर्धा करते हैं वैसे हालात 1975 में नहीं थे. यह जरूर था कि सरकारी विज्ञापनों के लिए डीएवीपी के दफ्तर के चक्कर जरूर अखबारों के संपादक लगाते. क्योंकि उस वक्त डीएवीपी का बजट सालाना दो करोड़ रुपए का था. लेकिन अब के हालात में तो विज्ञापन के लिए सरकारों के सामने खबरों को लेकर संपादक नतमस्तक हो जाते हैं क्योंकि हर राज्य के पास हजारों करोड़ के विज्ञापन का बजट होता है. इसे एक वक्त हरियाणा के सीएम हुड्डा ने समझा तो बाद में राजस्थान में वसुधंरा से लेकर बिहार में नीतीश कुमार से लेकर दिल्ली में केजरीवाल तक इसे समझ चुके हैं. यानी अब खबरों को स्थायी पूंजी की छांव भी चाहिए. लेकिन अबकी तुलना में चालीस बरस के कई हालात उल्टे भी थे. मसलन अभी संघ की सोच के करीबियों को रेडियो, दूरदर्शन से लेकर प्रसार भारती और सेंसर बोर्ड से लेकर एफटीआई तक में फिट किया जा रहा है तो चालीस साल पहले आपातकाल लगते ही सरकार के भीतर संघ के करीबियों और वामपंथियों की खोज कर उन्हें या तो निकाला जा रहा था या हाशिये पर ढकेला जा रहा था. वामपंथी धारा वाले आनंद स्वरूप वर्मा उसी वक्त रेडियो से निकाले गए. हालांकि उस वक्त उनके साथ काम करने वालों ने आईबी के उन अधिकारियों को समझाया कि रेडियो में कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो उसकी विचारधारा का कोई मतलब नहीं है क्योंकि खबरों के लिए पूल बनाए जाते हैं. यानी जो देश की खबरें जाएंगी उसके लिए पूल-वन, विदेशी खबरों के लिए पूल-टू. जिन खबरों को लेना है जब वह सेंसर होकर पूल में लिखी जा रही हैं और उससे हटकर कोई दूसरी खबर जा नहीं सकती तो फिर विचारधारा का क्या मतलब? आनंद स्वरूप वर्मा तो वैसे भी उस वक्त खबरों का अनुवाद करते हैं क्योंकि पूल में सारी खबरें अंग्रेजी में ही लिखी जाती हैं, तो अनुवादक किसी भी धारा का हो सवाल तो अच्छे अनुवादक का होता है. लेकिन तब अभी की तरह आईबी के अधिकारियों को भी अपनी सफलता दिखानी थी तो दिखाई गई.

मौजूदा वक्त में जैसे गुजरात के रिपोर्टरों या पीएम के करीबी पत्रकारों को अपने-अपने संस्थानों में जगह मिल रही है.

आपातकाल के वक्त मीडिया जिस तेवर से पत्रकारिता कर रहा था, आज उसी तेवर से मीडिया एक बिजनेस मॉडल में बदल चुका है, जहां सरकार के साथ खड़े हुए बगैर मुनाफा बनाया नहीं जा सकता है.

चालीस साल पहले आपातकाल के वक्त जे.पी. के आंदोलन पर नजर रखने के लिए खासतौर से तब बिहार में चाक-चौबंद व्यवस्था की गई.

करीब सौ समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन बंद कर झुकाया गया था. लेकिन तब भी स्टेटसमैन के सीआर ईरानी और एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका ने झुकने से इनकार कर दिया तो सरकार ने इनके खिलाफ चालें चलनी शुरू कीं. लेकिन पीएमओ के अधिकारी ही सेंसर बोर्ड में तब्दील हो गए. प्रेस परिषद भंग कर दी गई. आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक का अध्यादेश 1975 लागू कर दिया गया. यह अलग बात है कि इसके बावजूद चालीस साल पहले संघर्ष करते पत्रकार और मीडिया हाउस आपातकाल में भी दिखाई जरूर दे रहे थे. लेकिन चालीस साल बाद तो बिना आपातकाल सत्ता झुकने को कहती है तो हर कोई सरकारों के सामने लेटने को तैयार हो जाता है. ■■

पाक से रिश्तों में तल्खी

नजरिया उर्दू प्रेस का

■ राजश्री यादव

भारत-पाक संबंधों में फिर बढ़ती तल्खियों को लेकर उर्दू मीडिया ने चिंता जताई है और कहा है कि गत एक साल में आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास किए गए थे उन्हें जारी रखना चाहिए.

नई दिल्ली से प्रकाशित **'दावत'** ने लिखा है गत एक साल के दौरान भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रप्रमुखों ने एक-दूसरे के प्रति जिस अंदाज से गर्मजोशी का प्रदर्शन किया था और उसके नतीजे

राजनीतिक स्वार्थ ने दोनों देशों की तरफ से एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक बयानों का सिलसिला छेड़ रखा है.

में दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के सिलसिले में जो बात आगे बढ़ी थी, ऐसा महसूस होता है कि ये सारी कोशिशें व्यर्थ चली जाएंगी. आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए विश्वास की जो बर्फ थोड़ी बहुत पिघली थी, उससे कहीं ज्यादा नफरत और विवादों की परतें जम जाएंगी. कारण राजनीति और राजनीतिक स्वार्थ है, जिन्होंने दोनों देशों की तरफ से एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक बयानों का सिलसिला छेड़ रखा है. इसकी शुरुआत म्यांमार की जमीन पर आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय फौज की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से होता है. अखबार ने लिखा है दोनों ही देशों के लिए बेहतर यही है कि एक-दूसरे के खिलाफ जारी आक्रामक बयानों के सिलसिले को रोककर फिर से वैसी ही शुरुआत करें जिस तरह दोनों देशों के प्रमुखों ने गत एक बरस के दौरान की थी.

'मुंसिफ' डेली हैदराबाद ने लिखा है, दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली के 21 विधानसभा सदस्यों (विधायकों) के खिलाफ फौजदारी मामलों के तहत चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है. भारतीय राजनीति पर जुर्म और मुजरिम कितने हावी होते जा रहे हैं, ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है. बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि राजनीति और अपराधियों का चोली-दामन का साथ हो चुका है. देश की जनता को ये अफसोसनाक रुझान देखने को मिल रहा है कि जो जितना बड़ा गुंडा, बदमाश वो उतना ही कामयाब राजनेता है. कोई भी राज्य हो या कोई भी विधानसभा हो और संसद, किसी के ताल्लुक से भी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी सदन के सदस्यों में एक भी अपराधी नहीं है. गालिबन ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी विधानसभा के 21 सदस्यों पर फौजदारी मुकदमात दायर करने की तैयारी की जा रही है. अगर केजरीवाल और उनके बीस विधानसभा सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं तो उनमें चार्जशीट भी दाखिल होनी चाहिए और अदालत को फौरन दूध का दूध और पानी का पानी भी करना चाहिए. ■■

और अंत में...

उसकी पकड़ से दूर भला
कैसे जाओगे
सामान होगा साथ वही
जो कमाओगे
जितनी भी चाहो कर लो
अदाकारियां मगर
बच भी गए यहां तो
वहां बच न पाओगे

(साभार 'सहाफत डेली' दिल्ली)

नजर के पार

चीन का यही है वास्तविक चेहरा

रहीस सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

चीन ने संयुक्त राष्ट्र में 26/11 के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी पर पाकिस्तान का साथ देकर कम-से-कम भारत को यह संदेश दे दिया कि वह आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ नहीं है. चीन ने भले ही यह कहकर अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश की हो कि भारत ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं, यह संभव हो सकता है कि भारत उतने सबूत न दे पाया हो जितने कि चीन को चाहिए हों, लेकिन इसमें तो किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए कि जकी उर रहमान लखवी लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशन कमांडर है. जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज अल सईद का करीबी है. उस पर अलकायदा के सहयोगी होने तथा इराक व दक्षिण-पूर्व एशिया में आतंक फैलाने का आरोप रहा है. यही नहीं अलकायदा से जुड़े होने के कारण संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति ने 2008 में उसे आतंकी घोषित किया है. क्या चीन को इससे भी ऐतराज हो सकता है? क्या इस तरह से चीन संयुक्त राष्ट्र के उन प्रस्तावों (विशेषकर प्रस्ताव संख्या 1267) को गौण नहीं बना रहा जो आतंकी गतिविधियों को अवरुद्ध करने के लिए पारित हुए थे? आखिरी सवाल यह कि भारतीय कूटनीति को इस चीनी कृत्य को किस नजरिए से देखना चाहिए? क्या लखवी पर चीन के नजरिए को जानने के बाद यह कहना उचित होगा कि भारत का कूटनीतिक नेतृत्व पिछले कुछ दिनों से चीन के साथ मित्रता के क्षेत्र में छलांग लगाने की बात कर रहा था, वह गलत था?

जकी उर रहमान लखवी का मामला हो या अन्य वे सामरिक मामले जो भारत के लिए चिंता के विषय हैं तथा

पाकिस्तान की तरफ से पैदा किए जा रहे हैं, चीन का नजरिया भारत विरोधी या पाकिस्तान समर्थक का रहा है. चीन जब भी कभी किसी भी मंच पर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है तो भारत ऐसी असहजता व्यक्त करता है मानो ऐसा पहली बार हुआ हो, जो भारत के अनुमानों या अपेक्षाओं के विपरीत था. लेकिन भारत को ऐसा दो कारणों से लगता है. पहला यह कि चीन-पाकिस्तान संबंधों को देखते समय भारत का राजनीतिक व कूटनीतिक नेतृत्व प्रायः तदर्थवादी होता है इसीलिए वह उस समय उसी विषय तक सीमित रह जाता है, जो सामने आया है, जबकि उसे पाकिस्तान के साथ चीन के संबंधों की पूरी श्रृंखला पर गौर करने की जरूरत होती है. दूसरी बात यह है कि भारत बार-बार चीन को उसी आईने में देखने की कोशिश करता है जिस आईने से भारत को चीन दिखाना चाहता है. स्वाभाविक है कि भारत को अनपेक्षित कूटनीतिक पराजयों का सामना करना ही पड़ेगा. शुरू से ही चीन भारत के प्रति ऐसी रणनीति बनाकर चल रहा है जो भारत की एशिया में, विशेषकर दक्षिण एशिया अथवा दक्षिण-पूर्व एशिया में, भूमिका को सीमित कर दे. चीन पाकिस्तानी आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट कार्नर रखता है. ऐसी स्थिति में भारत को गंभीरता से विचार करना होगा कि वर्तमान समय में चीन भारत से सीधा टकराव नहीं चाहेगा बल्कि इन्हीं हथियारों (यानी पाकिस्तान आधारित आतंकी समूहों या पाकिस्तान के साथ रणनीतिक संबंधों) के जरिए भारत को हमेशा डिस्टर्ब रखने की रणनीति पर काम करेगा. ■■

तोल बोल

मौजूदा शासन में 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को 'ब्रेन डेड' घोषित कर दिया गया है. 26 मई 2014 को ही यह घोषणा हो गई थी.

■ **यशवंत सिन्हा**, भाजपा नेता

वसुंधरा राजे को भाजपा के नेता क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन क्लीन चिट जनता से मिलती है, नेताओं से नहीं.

■ **गिरिजा व्यास**, कांग्रेस नेता

gñWmnH$ gnmXH$: nd. Odmhabmb XS>m
M`a_Z, E[S>Qmo{a`b ~moS>© : {dO` XS>m
E{S>Qa-BZ-Mr\$: amOD> XS>m
gnmXH$: {dH$mg {_l★
★ nr. Ama. ~r. H$mZZ H$ AZgma gnU gnmXH$s` Xm{`Ëd H$ {bE {Oå_Xma.

© लोकमत समाचार _àH$m{eV g^r gm_J«r H$m gd©{YH$ma b _rS>`m àm`d{Q> {b. H$ nmg ga{jV h. bmoH$_V _rS>`m àm`d{Q> {b. H$ {bE _ÐH$ Ed àHmeH बालाजी मुले Ûmam bmoH$_V _rS>`m àm. {b., ßbmQ> H$. 192, 207, 208 E_. AmB. S>r. gr. BÊS>ñQ´>r`b E[a`m, ~Qr~mar, ZmJnya _ _{ÐV Ed bmoH$_V ^dZ n. Odmhabmb Zhê$ _mJ, ZmJnya _ àH$m{eV.
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XaÜd{Z : 0712-2423527 (7 bmBÝg) \°$Šg : 6618555
Email : gnmXH$s` : lsedit.ngp@lokmat.com
{dkmnZ : advt.ngp@lokmat.com {dVaU : circ.ngp@lokmat.com

इतिहास पर नजर 25 जून

वर्ष 1950 में आज ही के दिन उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया था. उत्तर कोरिया की सेनाएं कई जगहों से दक्षिण कोरिया में प्रवेश कर गईं. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सिंगमैन री ने संयुक्त राष्ट्र को बताया था कि कम से कम 36 उत्तर कोरियाई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से दक्षिण कोरिया की राजधानी की तरफ बढ़ रही हैं. उत्तर कोरिया ने इस हमले को जायज ठहराया और कहा कि उसने ये अपने बचाव में किया है. उसका कहना था कि हमला पहले दक्षिण कोरिया की तरफ से किया गया. कोरिया का विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान की सेनाओं के वापस चले जाने के बाद हुआ था. सोवियत संघ की सेनाएं उत्तरी कोरिया पर काबिज थीं और अमेरिकी सेनाएं दक्षिण कोरिया पर. उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध जुलाई, 1953 तक चला था. ■■

- ■1868-अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन में 8 घंटे काम करने का कानून बनाया.
- ■1932-भारत ने ब्रिटेन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला.
- ■1975-तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक आपातकाल लगाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
- ■1983-भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा कर पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया.

पाठकों के पत्र

बढ़ती किसान आत्महत्याएं

नई सरकार के पदारूढ़ होने के एक वर्ष बाद भी भारत में किसान आत्महत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. शोचनीय स्थिति यह है कि अब अमेरिका व फ्रांस जैसे विकसित देशों में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं. क्या यह हमारी सभ्यता पर बढ़ता संकट नहीं है? भारत में प्रत्येक 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है. किसान की आत्महत्या दोहरी मार करती है. एक तो गृहस्वामी की मृत्यु हो जाती है और साथ ही उस मौसम (सीजन) की फसल की भी हानि हो जाती है. हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों के लिए मुआवजे की राशि में वृद्धि कर दी है. राज्य सरकार का रिकार्ड बताता है कि महाराष्ट्र में पिछले सात महीनों में गत वर्ष की इतनी ही अवधि की बनिस्बत 40 प्रतिशत अधिक आत्महत्याएं हुई हैं. भारत के अन्य हिस्सों से भी ऐसे भयानक समाचार लगातार आ रहे हैं.

■ **बीनिश अहमद**, इंदौर

यमराज की सूची

हास्य

एक दिन यमराज एक लड़के के पास आए और बोले- ''लड़के, आज तुम्हारा आखरी दिन है!''

लड़का : ''लेकिन मैं अभी तैयार नही हूं.''

यमराज : ''ठीक है, लेकिन सूची में तुम्हारा नाम पहला है.''

लड़का : ''ठीक है , फिर क्यों न हम जाने से पहले साथ में बैठ कर चाय पी लें?''

यमराज : ''उचित है.''

लड़के ने चाय में नींद की गोली मिला कर यमराज को दे दी.

यमराज ने चाय खत्म की और गहरी नींद में सो गए.

लड़के ने सूची में से अपना नाम शुरुआत से हटा कर अंत में लिख दिया.

जब यमराज को होश आया तो वह लड़के से बोले : ''क्योंकि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसलिए मैं अब सूची अंत से चालू करूंगा..!''

इस कहानी की सीख है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता. अर्थात जो तुम्हारी किस्मत में है वह कोई नहीं बदल सकता चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो. इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा है- ''तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं. तू कर वह जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है.'' ■■